परमाणु बिजली का मोह घटा नहीं है

जापान के फुकुशिमा दाइची संयंत्र में हाल की दुर्घटना के बाद जहां कई देशों ने अपने परमाणु कार्यक्रम में ज़बर्दस्त कटौती की घोषणा की है, वहीं दर्ज़नों देशों ने नए सिरे से परमाणु बिजली हासिल करने में रुचि दिखाई है।

फुकुशिमा दुर्घटना के बाद जापान ने कहा है कि वह कोई नया परमाणु संयंत्र नहीं बनाएगा। इसी प्रकार से, जर्मनी ने परमाणु संयंत्रों को धीरे-धीरे बंद करने की घोषणा की है जबकि स्विट्ज़रलैण्ड ने कहा है कि वह अपने पुराने संयंत्रों की आयु पूरी हो जाने के बाद उनकी जगह नए संयंत्र नहीं लगाएगा। इटली ने भी पिछले सप्ताह परमाणु कार्यक्रम शुरू न करने का प्रस्ताव पारित किया है।

मगर इन खबरों का मतलब यह नहीं है कि दुनिया से परमाणु बिजली विदा होने को है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आंकड़े दर्शाते हैं कि दुनिया भर में 65 परमाणु बिजली घर निर्माणाधीन हैं। और इनमें वे संयंत्र शामिल नहीं हैं जो नियोजन के चरण में हैं या जिनके ठेके दे दिए गए हैं मगर निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इन आंकड़ों से यह भी पता नहीं चलता कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश परमाणु बिजली के आंगन में कदम रखने को तैयार हैं। जहां संयुक्त अरब अमीरात ने कोरिया इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन के साथ चार संयंत्र निर्माण का अनुबंध किया है, वहीं सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वह 2030 तक 16 परमाणु बिजलीघर बनाएगा।

इनके अलावा कई अन्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पास अपनी रुचि का पंजीयन कराया है। ऐसे देशों की संख्या 52 है, जिन्होंने हाल ही में एजेंसी से परमाणु बिजलीघर लगाने में मदद की गुहार की है। वैसे विशेषज्ञों का मत है कि इनमें से कई देश तो रुचि दिखाकर ही रह जाएंगे। इस संदर्भ में हंगरी के बुडापेस्ट विश्वविद्यालय की जेसिका ज्वेल का मत है कि किसी देश के लिए परमाणु बिजली अपनाने के लिए वहां कुछ आवश्यक परिस्थितियां मौजूद होनी चाहिए। जैसे वहां एक मज़बूत बिजली ग्रिड होनी चाहिए, स्थिर व कारगर सरकार होनी चाहिए और अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वह परमाणु संयंत्र की पूंजीगत लागत को वहन कर सके। जिन 52 देशों ने परमाणु बिजली में रुचि दिखाई है, उनमें से मात्र 10 ही इन तीनों शर्तों को पूरी करते हैं। इनके अलावा करीब 10 देश ऐसे हैं जहां उत्साह व संसाधन तो हैं मगर राजनैतिक अस्थिरता है। जैसे मिस्र के यही हाल हैं।

इसी दौरान कई निर्माणाधीन संयंत्रों का भविष्य अधर में है। जैसे फुकुशिमा के बाद चीन ने तय किया है कि वह वर्तमान संयंत्रों की सुरक्षा सम्बंधी समीक्षा करेगा और यह समीक्षा पूरी होने तक नए संयंत्रों के बारे में निर्णय लंबित रहेंगे। ***(स्रोत फीचर्स)***